tions of rice and imported edible oils under the scheme of Pulic Distribution system by the Central Government to the States/UTs are supplementary in nature and are also subject to the overall availability of stocks in the central pool, relative demands from various states, availability in the open market and other related factors. During the calendar year 1986 (upto November), an allocation of 2,75,000 tonnes of rice was made to Madhya Pradesh against the demand of 3,45,000 tonnes. As for edible oils, an allocation of 20,000 tonnes was made to MP against the demand of 62,000 tonnes during the oil year 1985-86 (November to Octobr).

As for Kerosene, requirements of States/UTs including MW are assessed by allowing a 5% growth over the allocations made in the corresponding period of the previous year on a four-month block basis and allocations are made accordingly.

During the last four quarters, this allocation has been enhanced to 7½% in case of all the States/UTs including M.P. Besides, ad-hoc allocations are also made to meet specific situations like flood, drought, cyclon shortages of LPG/soft coke etc. During the calendar year 1986, a total allocations of 2,94,521 tonnes of kerosene (including ad-hoc allocation) was made to Madhya Pradesh.

कालिन्दी कालोनी के समीप यमुना नदी पर पुल

492. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी पर कालिन्दी कालोनी के निकट नोएडा निवासियों की सुविधा के लिए किसी पुल के निर्माण का सुझाव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) सरकार कब तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली वृहद योजना में प्रस्तावित प्रारुप विस्तृत संशोधनों में दिल्ली स्थित कालिन्दी कालोनी के समीप यमुना नदी पर किसी पुल के निर्माण के बारे में विचार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत चौकीदार

493. **श्री रामचन्द्र विकल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली में कार्यरत चौकीदारों से 8 घंटे के बजाय 16 घंटे की ड्यूटी करवाई जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस वर्ष के दौरान में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अभ्यावेदनों पर हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों को अब तक समयोपरि भत्ते का भुगतान नहीं किया